एक नजर में

पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना घायलों को मिलेगा कैशलेस उपचार

नवभारत न्यूज

खंडवा। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पीएम राहत योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओपी जुगतावत ने बताया कि इस योजना के तहत डेजिग्नेटेड और नॉन-डेजिग्नेटेड अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जाएगी। डेजिग्नेटेड अस्पताल वे होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑर्थोपेडिक्स एवं पॉलीट्रॉमा जैसी विशेषज्ञ सेवाओं से जुड़े हैं और योजना से संबद्ध हैं। वहीं, नॉन-डेजिग्नेटेड अस्पताल वे होंगे जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं और स्टेबलाइजेशन पैकेज के तहत प्राथमिक उपचार प्रदान करेंगे।

जिले में इन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा- खंडवा जिले में श्रीमाली हॉस्पिटल, एसएनजी हॉस्पिटल, जिनाली आई हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल, गुर्जर हॉस्पिटल, हिंदूजा हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, शुभम हॉस्पिटल, रिचर्ड पेंपुरी हॉस्पिटल, नवोदय हॉस्पिटल, श्री साईं केयर हॉस्पिटल (बोरगांव बुजुर्ग), न्यू लाइफ हॉस्पिटल, स्वर्णिम आई केयर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नर्मदा हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल, गार्गी लाइफ केयर हॉस्पिटल (सिंगोट), साईंवान हॉस्पिटल, श्री दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ईप्सा एंडोस्कोपी एंड लेजर सर्जिकल सेंटर, अत्रीवाल हॉस्पिटल, जैन नर्सिंग होम सहित अन्य अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

दुग्ध संघ सचिवों का प्रबंधन एवं लेखांकन पर प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज

खंडवा। इंदौर दुग्ध सहकारी संघ के सहयोग से जिला सहकारी संघ खंडवा द्वारा बुरहानपुर जिले की दुग्ध सहकारी संस्थाओं के सचिवों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 7 मार्च 2026 तक होटल पंचवाटिका, बुरहानपुर में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के संचालन, प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर दुग्ध सहकारी संघ के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक एनके पगारे और इंदौर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के पूर्व प्राचार्य केएल राठौर उपस्थित रहे। जिला सहकारी संघ के प्रबंधक मेहताब सिंह भदोरिया ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिचय देते हुए संघ द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान एनके पगारे ने दुग्ध सहकारी संस्थाओं में लेखांकन पद्धति, अभिलेखों के रखरखाव और नियमित लेखांकन के महत्व पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। वहीं के.एल. राठौर ने संस्थाओं की प्रबंधन व्यवस्था, बैठक की प्रक्रिया, निर्वाचन, ऑडिट तथा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के लिए जिला स्तरीय समिति गठित

नवभारत न्यूज

खंडवा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के मामलों की जांच और अनुशंसा के लिए प्रदेश सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के गठन के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समिति के उपाध्यक्ष होंगे, जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वर्षा शिवपुरे ने बताया कि समिति में आईटीडीपी परियोजना निदेशक, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री, उपसंचालक कृषि तथा मध्यप्रदेश जल निगम के महाप्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। समिति शासन के मापदंडों के आधार पर पेयजल संबंधी आवश्यक कार्यों की अनुशंसा करेगी तथा एकल ग्राम नलजल योजनाओं के असफल स्रोतों के स्थान पर नए सफल स्रोत विकसित करने के संबंध में भी निर्णय लेगी।

सरसों की फसल का भावांतर पंजीयन 20 तक

नवभारत न्यूज

खंडवा। सरसों उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। किसान 20 मार्च तक ई-उपार्जन पोर्टल पर अपनी सरसों फसल का पंजीयन करा सकते हैं।

उप संचालक कृषि नितेश यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। भावांतर योजना के तहत जिले में गेहूं और चना पंजीयन केंद्रों की तर्ज पर कुल 72 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां किसान अपने नजदीकी समिति कार्यालय में जाकर पंजीयन करा सकते हैं।

उप संचालक कृषि यादव ने जिले के सभी सरसों उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी फसल का पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि शासन की भावांतर योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

रूपल जायसवाल को यूपीएससी में 43वीं रैंक

विधि में ग्रेजुएट रूपल ने आईएएस बनने के लिए ठुकराया था 22 लाख रुपए सालाना का पैकेज

नवभारत न्यूज

खंडवा। शहर की महादेवी नगर की प्रतिभावान बेटी रूपल जायसवाल ने संघ लोक सेवा आयोग 2025 के परिणामों में राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं रैंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। इस शानदार सफलता के साथ रूपल का भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने का सपना साकार हो गया है।

इससे पूर्व, उन्होंने 2024 में 512वीं रैंक प्राप्त की थी, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय ने उन्हें देश के शीर्ष रैंक धारकों की सूची में ला खड़ा किया। लॉ ग्रेजुएट रूपल ने यूपीएससी की तैयारी के लिए मुंबई की एक नामी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में मिल रहे 22 लाख रुपये सालाना के पैकेज को ठुकरा दिया था। पहले प्रयास में वे प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थीं। तीसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा के दौरान उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन परिवार के समर्थन और इच्छाशक्ति के बल पर उन्होंने परीक्षा दी और आज इतिहास रच दिया। रूपल ने साबित कर दिया

कि बिना किसी महंगी कोचिंग के भी सफलता के शिखर पर पहुँचा जा सकता है। उन्होंने किसी भी संस्थान का सहारा न लेते हुए, केवल प्रामाणिक पुस्तकों और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से घर पर ही पढ़ाई की। सिविल इंजीनियर पिता धनंजय जायसवाल और पूरे परिवार ने उनकी इस कठिन यात्रा में ढाल बनकर साथ दिया।

साक्षात्कार में कानूनी सूझबूझ का परिचय : - इंटरव्यू के दौरान रूपल की 'लॉ' पृष्ठभूमि के आधार पर उनसे 'तलाक और भरण-पोषण' से जुड़ा एक अत्यंत पेचीदा सवाल पूछा गया। सवाल था कि यदि 20 हजार करोड़ की संपत्ति वाला पति बिना किसी आरोप के तलाक लेना चाहे, तो आधार क्या होगा और भरण-पोषण कितना मिलना चाहिए?

रूपल ने बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया कि आधार 'आपसी सहमति' हो सकता है। भरण-पोषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पत्नी की आय और बच्चों की कस्टडी जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जब बोर्ड ने पति की आय का 50% भरण-पोषण देने पर क्रॉस क्वेश्चन किया, तो रूपल ने बड़ी परिपक्वता से उत्तर दिया कि 'भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी को सम्मानजनक जीवन देना है, न कि पति को सजा देना।' उनके इस तार्किक और संतुलित उत्तर ने बोर्ड का मन जीत लिया।

नीति आयोग डिप्टी सेक्रेटरी ने आंगनवाड़ी, अस्पताल और एनआरसी का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

खंडवा। केंद्र सरकार के नीति आयोग की डिप्टी सेक्रेटरी नेहा नौटियाल ने शुक्रवार को खंडवा जिले का दौरा कर आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने संपूर्णता अभियान-2.0 के तहत आकांक्षी जिला खंडवा और आकांक्षी ब्लॉक छैगांवमाखन में विभिन्न विभागों की प्रगति का मैदानी स्तर पर जायजा लिया।

जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी केआर कानूडे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नौटियाल ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और पशुपालन विभाग से संबंधित इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से डाइट कॉलेज में निर्मित आईटी लैब का भी अवलोकन किया।

नौटियाल ने दौंदवाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की ऊंचाई और वजन मापन की प्रक्रिया देखी तथा कुपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने छैगांवमाखन स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां आयोजित टीबी शिविर की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने देशगांव की शासकीय माध्यमिक शाला का भी भ्रमण कर बच्चों से चर्चा की और स्वच्छता तथा हाथ धोने की आदत पर जोर दिया। दौरे के बाद उन्होंने कलेक्टर ऋषव गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा से भेंट कर संपूर्णता अभियान-2.0 के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

सहकारिता गबन पर कलेक्टर सख्त

करोड़ों रुपए डकारने वाले घोटालेबाजों से करेंगे सख्ती से वसूली, ऑडिटर्स भी शक के घेरे में

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले में सहकारिता के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के बड़े खेल पर अब प्रशासन ने सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए सहकारिता विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि सहकारी समितियों और बैंकों में हुए गबन की राशि दोषियों से हर हाल में समय-सीमा के भीतर वसूली जाए।

जिले में पिपलानी के करोड़ों के घोटाले और हाल ही में नहालदा रामेश्वर सोसाइटी में सामने आए 1.10 करोड़ के गबन ने विभाग की साख को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि इन गंभीर मामलों में जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौन साधे हुए थे, जिससे उनकी कार्यप्रणाली और मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे भ्रष्टाचार की जड़ों में उन ऑडिटर्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिनकी निगरानी में सालों से यह बंदरबांट चलती रही। कलेक्टर के सख्त तेवरों ने अब यह संकेत दे दिया है कि केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि अब सीधी वसूली और जेल की राह दोषियों का इंतजार कर रही है।

कलेक्टर ने सिर्फ सहकारिता ही नहीं, बल्कि जिले की कानून व्यवस्था पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने ओंकारेश्वर में अवैध शराब की बिक्री और मिलावटखोरी पर कड़ा प्रहार करने के साथ ही सभी एसडीएम को रेत के अवैध भंडारण और अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल सड़क पर उतरने के निर्देश दिए हैं।

शहर में यातायात बाधित करने वाले बड़े वाहनों की अवैध पार्किंग पर भी नगर निगम और पुलिस का संयुक्त दस्ता कार्रवाई करेगा। माह के प्रथम गुरुवार को होने वाली समीक्षा बैठक प्रशासन की सक्रियता का पैमाना बनेगी। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में सरकारी धन की सुरक्षा और जनता का हित ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।

सद्भावना मंच ने किया होली और रंगपंचमी मिलन समारोह

नवभारत न्यूज

खंडवा। सद्भावना मंच के सदस्यों द्वारा माली कुआं स्थित मंच कार्यालय में संस्थापक प्रमोद जैन की उपस्थिति में होली एवं रंगपंचमी मिलन समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं।

मंच के निर्मल मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर संस्थापक प्रमोद जैन ने कहा कि होली का पर्व नफरत मिटाकर प्रेम, भाईचारे और खुशियों के रंग फैलाने का संदेश देता है। उन्होंने सभी को आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष पूर्व डीएसपी आनंद तोमर, जगदीशचंद्र चौरे, नरेंद्र दवे, सुनील सोमानी, जीडी श्राफ, त्रिलोक चौधरी, गणेश भावसार, राधेश्याम शाक्य सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान कुछ सदस्यों ने होली गीतों पर कराओके के साथ संगीतमय प्रस्तुतियां भी दीं।

भाजपा की गुटबाजी दिखाई दी सड़क पर

जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े का छलका दर्द, अपनों ने ही बैठक से रखा 'आउट'

नवभारत न्यूज

खंडवा। खंडवा भाजपा में सबकुछ ठीक नहीं है की चर्चाएं अब बंद कमरों से निकलकर सरेआम होने लगी हैं। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित आजीवन सदस्यता निधि की महत्वपूर्ण बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ते-चढ़ते बची, जब जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े ने संगठन में खुद को दरकिनार किए जाने पर खुलेआम मोर्चा खोल दिया। सत्ता और प्रशासन में पहले ही हाशिए पर चल रहीं वानखेड़े ने भारी सभा में माइक थामकर दो-टूक कहा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन मुझे पार्टी की बैठकों की सूचना तक नहीं दी जाती। मेरे साथ जो हो रहा है, वह गलत है।

जिलाध्यक्ष ने मांगी माफी, महामंत्री पर फोड़ा ठीकरा : अध्यक्ष की तीखी आपत्ति से असहज हुए जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद जताते हुए माफी मांगी और स्वीकार किया कि वानखेड़े एक सम्मानित पद पर हैं। जिलाध्यक्ष ने इस चूक का ठीकरा जिला महामंत्री धर्मेंद्र बजाज के सिर फोड़ते हुए कहा कि सूचना देने की जिम्मेदारी उनकी थी। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस 'चूक' को महज तकनीकी गलती नहीं, बल्कि गहरी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है।

पार्टी के भीतर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पूरा मामला विधायक कंचन तनवे और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान का नतीजा है। दरअसल, महामंत्री धर्मेंद्र बजाज को विधायक का बेहद करीबी माना जाता है। चर्चा है कि इसी 'करीबी' के चलते जानबूझकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर जिला पंचायत अध्यक्ष को सूचना नहीं दी गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष की यह सार्वजनिक नाराजगी भाजपा के उस दावे की हवा निकाल रही है जिसमें 'अनुशासन' की बात कही जाती है। अपनों के ही बीच उपेक्षा का शिकार होने का यह दर्द अब पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है।

बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर जिला स्तरीय बैठक

नवभारत न्यूज

खंडवा। बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति और पुनर्वास के लिए गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स तथा बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर केआर बडोले की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में सहायक श्रम अधिकारी अनिल मलगाया, डिप्टी कलेक्टर दिनेश सावले, महिला थाना निरीक्षक सुलोचना गहलोत, विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रभारी सुनीता जोसेफ, अग्रणी जिला प्रबंधक गणेश तईकर, सीडीपीओ गोपाल मोरे, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, श्रम निरीक्षक नवीन कुमार गढ़ेकर व खुशबू मंडलोई सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में बाल श्रम उन्मूलन व पुनर्वास की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

कबड्डी सहित पारंपरिक खेलों की स्पर्धाएं शुरू

नवभारत न्यूज

खंडवा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों की टीमें भाग ले रही हैं।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह में खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार राय, वन मंडलाधिकारी राकेश डामोर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ नागार्जुन गौड़ा, पंधाना जनपद अध्यक्ष सुमित्रा काले, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल तथा धर्मेंद्र बजाज सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के

चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन नीरज पाराशर ने किया।

इस अवसर पर महापौर अमृता अमर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता जैसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निमाड़ क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और विशेष रूप से कुश्ती में यहां के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की।

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि खेल प्रतियोगिताएं हमें खेल भावना और टीम भावना का महत्व सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेल युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

जिला पंचायत के सीईओ डॉ नागार्जुन गौड़ा ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें खो-खो, कबड्डी और कुश्ती की विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं।